

# सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाएँ

## (क) राज्य योजनाएँ

### (1) वृद्धावस्था पेंशन योजना

#### Old age Pension Scheme

##### उद्देश्य

बेसहारा वृद्धों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना ।

##### पात्रता

ऐसे वृद्ध व्यक्ति जिनकी आयु 60 वर्ष या इस से अधिक है तथा उनकी देख रेख / पालन पोषण का उचित साधन न हो तथा जिनके अव्यस्क बच्चे हो व जिनकी वार्षिक आय समस्त स्रोतों से 35,000/- रू० से अधिक न हो ।

##### अथवा

ऐसे वृद्ध व्यक्ति जिनके परिवार की वार्षिक आय समस्त स्रोतों से 35000/-रू० से अधिक न हो ।

##### सहायता

60 वर्ष से 69 वर्ष की आयु के पेंशनरों को 750/- रू० प्रतिमाह ।

70 वर्ष या इससे अधिक आयु के पेंशनरों को 1300/- रू० प्रतिमाह ।

##### प्रक्रिया

निर्धारित प्रपत्र पर पात्र व्यक्ति को अपना प्रार्थना पत्र सम्बन्धित पंचायत अथवा तहसील कल्याण अधिकारी या जिला कल्याण अधिकारी को प्रस्तुत करना होता है। पात्र व्यक्तियों की पहचान सम्बन्धित ग्राम सभा की बैठक में की जाती है तथा पहचान करके पात्र व्यक्तियों की सूची सम्बन्धित तहसील कल्याण अधिकारी को प्रस्ताव सहित भेजते हैं। सम्बन्धित तहसील कल्याण अधिकारी द्वारा पात्र व्यक्तियों के प्रार्थना पत्र तथा उसमें औपचारिकताएं अपने स्तर पर पूर्ण करवायी जाने उपरान्त प्रार्थना पत्रों को स्वीकृति हेतु सम्बन्धित जिला कल्याण अधिकारी को भेजा जाता है। 70 वर्ष से अधिक आयु के प्रार्थी अपने प्रार्थना पत्र सीधे तहसील कल्याण अधिकारी कार्यालय को दे सकते हैं।

##### सम्पर्क अधिकारी

जिला कल्याण अधिकारी/ तहसील कल्याण अधिकारी ।

(2)

## अपंग राहत भत्ता

### **Disability Relief Allowance**

उद्देश्य

अपंग व्यक्तियों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना ।

पात्रता

ऐसे अपंग व्यक्ति जिन्हें "व्यक्ति जिनमें अक्षमताएँ हैं (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण , एवं पूर्ण भागीदारी)" अधिनियम 1995 की धारा 2 में अपंगता की परिभाषा के अनुसार गठित चिकित्सा बोर्ड से जिन्हें 40 प्रतिशत या इस से अधिक स्थाई अपंगता प्रमाण पत्र जारी किया गया हो तथा जिनके कोई भी व्यस्क बच्चे न हो तथा वार्षिक आय समस्त स्रोतों से 35,000/- रू० से अधिक न हो । चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा जारी विकलांगता प्रतिशतता प्रमाण –पत्र चाहे वह सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार की विकलांगताओं के मूल्यांकन तथा प्रमाणित करने हेतु जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार बहु-विकलांगता 40 प्रतिशत या इससे अधिक प्रमाणित की गई हो, अपंग राहत भत्ता स्वीकृति हेतु मान्य है ।

मानसिक रूप से अविकसित व्यक्तियों को तथा 70 प्रतिशत या इससे अधिक अपंगता वाले व्यक्तियों को बिना किसी आय सीमा के पेंशन प्रदान की जाती है ।

सहायता

**40 से 69 प्रतिशत अपंगता वाले पेंशनरों को 750/- रू० प्रतिमाह ।**

**70 प्रतिशत या इससे अधिक अपंगता वाले पेंशनरों को 1300/- रू० प्रतिमाह ।**

**70 वर्ष या इससे अधिक आयु के अपंग पेंशनरों को 1300/- रू० प्रतिमाह ।**

प्रक्रिया

निर्धारित प्रपत्र पर पात्र व्यक्ति को अपना प्रार्थना पत्र सम्बन्धित पंचायत अथवा तहसील कल्याण अधिकारी या जिला कल्याण अधिकारी को प्रस्तुत करना होता है । पात्र व्यक्तियों की पहचान सम्बन्धित ग्राम सभा की बैठक में की जाती है तथा पहचान करके पात्र व्यक्तियों की सूची सम्बन्धित तहसील कल्याण अधिकारी को प्रस्ताव सहित भेजते हैं । सम्बन्धित तहसील कल्याण अधिकारी द्वारा पात्र व्यक्तियों के प्रार्थना पत्र तथा उसमें औपचारिकताएं अपने स्तर पर पूर्ण करवायी जाने उपरान्त प्रार्थना पत्रों को स्वीकृति हेतु सम्बन्धित जिला कल्याण अधिकारी को भेजा जाता है । 70 प्रतिशत या इससे अधिक अपंगता वाले प्रार्थी अपने प्रार्थना पत्र सीधे तहसील कल्याण अधिकारी / जिला कल्याण अधिकारी कार्यालय को दे सकते हैं ।

सम्पर्क अधिकारी

**जिला कल्याण अधिकारी/ तहसील कल्याण अधिकारी ।**

(3)

### विधवा/परित्यक्ता/एकल नारी पेंशन योजना

### **Pension Scheme for Widow/ Deserted / Single Women**

उद्देश्य

विधवा/परित्यक्त/एकल महिलाओं को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना ।

पात्रता

ऐसी महिला जो विधवा, परित्यक्ता अथवा 45 वर्ष से अधिक आयु की एकल नारी हो तथा जिनकी देख-रेख / पालन-पोषण का उचित साधन न हो तथा न ही व्यस्क पुत्र हो व उनकी वार्षिक आय समस्त स्रोतों से 35,000/- रू० से अधिक न हो ।

**अथवा**

ऐसी विधवा/परित्यक्ता/एकल नारी जिनके परिवार की वार्षिक आय समस्त स्रोतों से 35,000/- रू० से अधिक न हो ।

सहायता

**750/- रू० प्रतिमाह**

**70 वर्ष या इससे अधिक आयु की विधवा पेंशनरों को 1300/- रू० प्रतिमाह ।**

प्रक्रिया

निर्धारित प्रपत्र पर पात्र व्यक्ति को अपना प्रार्थना पत्र सम्बन्धित पंचायत अथवा तहसील कल्याण अधिकारी या जिला कल्याण अधिकारी को प्रस्तुत करना होता है। पात्र व्यक्तियों की पहचान सम्बन्धित ग्राम सभा की बैठक में की जाती है तथा पहचान करके पात्र व्यक्तियों की सूची सम्बन्धित तहसील कल्याण अधिकारी को प्रस्ताव सहित भेजते हैं। सम्बन्धित तहसील कल्याण अधिकारी द्वारा पात्र व्यक्तियों के प्रार्थना पत्र तथा उसमें औपचारिकताएं अपने स्तर पर पूर्ण करवायी जाने उपरान्त प्रार्थना पत्रों को स्वीकृति हेतु सम्बन्धित जिला कल्याण अधिकारी को भेजा जाता है।

सम्पर्क अधिकारी

**जिला कल्याण अधिकारी/ तहसील कल्याण अधिकारी ।**

(4)

## कुष्ठ रोगियों को पुर्नवास भत्ता

### Rehabilitation Allowance to Lepers

उद्देश्य

कुष्ठ रोगिया सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना ।

पात्रता

ऐसे कुष्ठ रोगी जो किसी सरकारी/अर्ध सरकारी/ निगमों/बोर्डों इत्यादि में कार्यरत न हो तथा स्वास्थ्य विभाग के उपचाराधीन हों को कुष्ठ रोगी पुनर्वास भत्ता प्रदान किया जाता है । भत्ता प्राप्त करने के लिए आयु तथा आय सीमा लागू नहीं है ।

सहायता

750/— रू० प्रतिमाह ।

70 वर्ष या इससे अधिक आयु के कुष्ठ रोगियों को 1300/— रू० प्रतिमाह ।

प्रक्रिया

कुष्ठ रोगी को भत्ता प्राप्त करने के लिए निर्धारित प्रपत्र पर आवेदन करना होता है जिसके साथ स्वास्थ्य विभाग से कुष्ठ रोग उपचाराधीन प्रमाण पत्र संलग्न करना होता है । सम्बन्धित तहसील कल्याण अधिकारी द्वारा पात्र व्यक्तियों के प्रार्थना पत्र तथा उसमें औपचारिकताएं अपने स्तर पर पूर्ण करवायी जाने उपरान्त प्रार्थना पत्रों को स्वीकृति हेतु सम्बन्धित जिला कल्याण अधिकारी को भेजा जाता है ।

सम्पर्क अधिकारी

जिला कल्याण अधिकारी/ तहसील कल्याण अधिकारी ।

(5)

## ट्रांसजैन्डर पेंशन योजना

### **Transgender Pension Scheme**

उद्देश्य

सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना ।

पात्रता

ऐसे ट्रांसजैन्डर जो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा अधिसूचित राज्य स्तरीय / जिला स्तरीय चिकित्सा बोर्ड द्वारा पहचान किए गए हों, बिना किसी आयु तथा आय सीमा के ट्रांसजैन्डर पेंशन हेतु पात्र हैं ।

सहायता

**750/- रू0 प्रतिमाह ।**

**70 वर्ष या इससे अधिक आयु के ट्रांसजैन्डर पेंशनरों को 1300/- रू0 प्रतिमाह ।**

प्रक्रिया

ट्रांसजैन्डर के मामले में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा अधिसूचित राज्य स्तरीय चिकित्सा बोर्ड द्वारा पहचान सम्बन्धी जारी प्रमाण-पत्र तथा स्वयं घोषित शपथ-पत्र सम्बन्धित तहसील कल्याण अधिकारी द्वारा पात्र व्यक्तियों के प्रार्थना पत्र तथा उसमें औपचारिकताएं अपने स्तर पर पूर्ण कार्रवाई की जाने उपरान्त प्रार्थना पत्रों को स्वीकृति हेतु सम्बन्धित जिला कल्याण अधिकारी को भेजा जाता है ।

सम्पर्क अधिकारी

जिला कल्याण अधिकारी/ तहसील कल्याण अधिकारी ।

\*\*\*\*\*